प्रवक,

एस० रामास्वामी प्रमुख संचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

देहरादूनः दिनांक । १ फरवरी, 2013

विषय:- मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन पी.आई.एल. संख्या 45/2012 "वनाग्नि की रोकथाम तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में ''वनाग्नि की रोकथाम तथा वन एवं वन्य जीव संरक्षण'' के संबंध में दिनांक 23 जनवरी, 2013 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में वनाग्नि की रोकथाम हेतु

निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित की जाय :-

(I) उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत किये जाने वाले वनीकरण के सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट बनायी जाय तथा वनीकरण कार्यक्रम की जी०पी०एस० लोकेशन अंकित की जाय। वनीकरण कार्यक्रम तथा वनाग्नि सुरक्षा कार्य का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तृतीय पक्ष (स्वतंत्र संस्थाओं / व्यक्तियों) से कराया जाय तथा उत्तराखण्ड वन विभाग की वेब साइट पर इसको प्रदर्शित किया जाय।

(III) चीड़ बहुल क्षेत्रों में चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट बनाने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाय तथा सर्वप्रथम ग्रामवासियों को स्थानीय रूप से इसके उपयोग के सम्बन्ध में अधिक

से अधिक जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाये जायं।

(III) प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने—अपने प्रभाग के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामसभा में वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत रेंज स्तर पर प्रत्येक ग्राम/स्कूल/सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार—प्रसार कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाय, जिससे अगली पीढ़ी वन व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सके।

(IV) वन अग्नि सुरक्षा हेतु वांछित बजट को माह जनवरी के अन्त तक अग्निकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रत्येक दशा में शासन स्तर पर अवमुक्त कर दिया जायेगा, जिससे अग्निकाल शुरू होने से पूर्व ही समस्त सुरक्षात्मक कार्य कर लिये जायें तथा अग्निकाल के दौरान पैसे के अभाव में कोई विपरीत प्रभाव न पड़ सके तथा पूर्ण रूप से अग्नि पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। बजट उपलब्धता में देरी की स्थिति में कैम्पा निधि से बजट प्राविधान / पिछले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान की सीमा के सापेक्ष एवं अवमुक्त बजट का समावेश करते हुए शेष राशि से अनाधिक धनराशि तक तुरन्त बजट का आबंटन करा कर कार्य समय से पूर्ण कर लिये जायें तथा कैम्पा निधि से आहरित की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति वनाग्नि हेतु प्राप्त बजट से कर ली जाये।

- (v)वन अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निकाल से पूर्व ही वनाग्नि नियंत्रण हेतु Modern Fire Fighting Equipments प्रदान किये जायँ। जैसे— सर्चलाईट, हैडलाईट (LED), फायर प्रुफ जैकेट, ड्रैस, टूल्स व अन्य नवीन उपकरण। क्रू—स्टेशन में तैनात कर्मचारियों को भारी उपकरणों के स्थान पर भारतीय अनुसंधान संस्थान (FRI) द्वारा विकसित हल्के व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें, ताकि कर्मचारी सुगमता से शीध्र ही आग पर नियंत्रण कर सकें।
- (vi) अग्निकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रत्येक वन पंचायत को पूर्व में प्रयुक्त होने वाले भारी उपकरणों के स्थान पर भारतीय अनुसंधान संस्थान (FRI) द्वारा विकसित हल्के व आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें, ताकि कर्मचारी सुगमता से शीध्र ही आग पर नियंत्रण कर सके।
- (VIII) प्रत्येक वन प्रभाग वन अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित निर्देशिका के अनुसार अपने—अपने प्रभाग की कार्ययोजना बनायेगा तथा जिसमें प्रत्येक अधिकारी एवं ग्राम प्रधान/ वौलिन्टियर/स्वयं सेवी संस्थायें/थाना आदि के दूरभाश नं0 एवं मोबाईल नं0/ प्रचारित—प्रसारित किये जायंगे।
- (VIII) वनों से गुजरने वाले मार्गों एवं रेल पटरियों के किनारे झाड़ियों आदि की सफाई करने एवं प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के प्रयास किये जायें, ताकि राहगीर जंगलों में जलती बीडी, सिगरेट आदि न फेंके।
- (IX) वनों के अन्तर्गत फायर लाइनों की संफाई आदि कार्ययोजना के अनसार करा ली जाये तथा उसमें उग आई झाडियां तथा छोटे वृक्षों को काट कर फायर लाइनों को पूरी तरह से साफ कर लिया जाय। इसी प्रकार मार्गों के किनारे, पगडंडियों के किनारे, झाड़ियों तथा गिरी पत्तियों को साफ किया जाये।
- (x) प्रत्येक वन प्रभाग में स्थापित फायर कन्ट्रोल रूम से आग की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय क्रू—स्टेशन तक शीघ्र पहुंचायी जाये, जिससे क्रू—स्टेशन में उपस्थित कर्मचारी कम से कम समय में आग से प्रभावित क्षेत्र में पहुँच कर आग पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। इस संबंध में response time के norms निर्धारित किए जाएँ एवं सुस्पष्ट मानक कार्य प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures) बनाए जाएँ। क्रू—स्टेशन में फायर वाचर की संख्या स्थानीय रूप से बढ़ाए जाने पर विचार किया जाय, ताकि उस क्षेत्र से परिचित स्थानीय फायर वाचर अधिक सुगमता से आग पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें।
- (XI) आग के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाये, जिससे बच्चे इसके सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर वनाग्नि से होने वाली क्षति को कम से कम करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकें।
- (XIII)वनाग्नि काल में सभी संबंधित विभाग यथा चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, गृह विभाग आदि वन विभाग को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करेंगे।
- (XIII) वन विभाग के अन्तर्गत पर्याप्त अग्निरोधी टीमों का गठन कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए, उनके अनुभव एवं उनकी कार्यक्षमता के अनुरूप सहयोग प्राप्त किये जाये।
- (XIV) वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्र में, यदि किसी दैनिक कर्मचारी / स्थानीय नागरिक की आग बुझाते हुए या अन्यथा आग की चपेट में आकर मृत्यु हो जाती है तो, उस प्रकरण की जांच करा कर सम्बन्धित को दैवीय आपदा मद से सहायता दी जाय। इस संबंध में

D/Note & Drft/F-3/JFeb/G.O.Let/2013

आपदा प्रबन्धन विभाग स्पष्ट आदेश भी जारी करें। इसी क्रम में यदि कोई विभागीय कर्मचारी की मृत्यु, आग बुझाते समय हो जाती है, तो उसको नियमानुसार सहायता दी जाय।

(xv) ग्रामीण समुदाय की लकड़ी पर निर्भरता कम करने के लिए शीघ्र व आसान गैस उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं कुछ अनुदान अनुमन्य कराने पर विचार किया जाय। पिरूल के बिक्रेट को बढ़ावा देने हेतु इसमें भी आंशिक सब्सिडी प्रदान करने पर विचार किया जाय।

(XVI)वनाग्नि सुरक्षा कार्य में पुलिस के अग्निशमन विभाग से पूरा सहयोग लिया जाय तथा सहयोग मांगने पर मना नहीं किया जाय। वनाग्नि जनित दुर्घटना होने पर 108 की सहायता प्राप्त की जाय।

(XVIII) फायर वाचर्स व वनाग्नि सुरक्षा कर्मियों के बीमा की व्यवस्था भी की जाय।

(XVIII)वनाग्नि सुरक्षा कार्यों के प्रचार-प्रसार की योजना बनाई जाय। इस संबंध में सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किये जायं, बडे साईन बोर्ड लगाये जायं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाय।

2

भवदीय

(एस० रामास्वामी) प्रमुख सचिव

संख्या २२६७/ x-3-13 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (i) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबन्धन, उद्योग, शिक्षा, वित्त, अर्जा राजस्व, नागरिक आपूर्ति, सूचना व गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (॥) आयुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- (॥) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (IV) प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
- (v) प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
- (vi) मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता व विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी, नैनीताल।
- (🗥 निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड।

(VIII) गार्ड फाईल।

(1x) अनुभाग किष्यकारी, वन-2

आज्ञा से

अपर सचिव